भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4679

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

एनएचएआई द्वारा लाया गया इनविट इश्यू

†4679. श्री यूसुफ पठान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के निर्गमों में खुदरा निवेशकों के लिए 25,000 करोड़ रुपये मूल्य की इकाइयाँ अलग रखने का निर्णय लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के ठेके देने में सबसे कम बोली लगाने वाले की प्रणाली को छोड़ने से पक्षपात या लागत में वृद्धि के आरोप लग सकते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए किन तंत्रों की योजना बनाई जा रही है;

(घ) राजमार्गों के मौद्रीकरण के लिए पारंपरिक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल से इनविट मॉडल में स्थानांतरण के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसे निजीकरण के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में कोई स्वतंत्र आर्थिक प्रभाव अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (एनएचआईटी) के अतिरिक्त एक सार्वजनिक इनविट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के (बंडल) का आकार या खुदरा निवेशकों के लिए प्रस्ताव की सीमा अभी तय की जानी है।

(ख) और (ग) सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) में गुणवत्ता, मात्रा और डिज़ाइन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में बार-बार बदलाव होते रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एच-1 बोलीदाता के आधार पर डीपीआर परामर्शी का कार्य सौंपने पर विचार कर रही है, जिसका निर्णय क्यूसीबीएस (गुणवत्ता और लागत आधारित चयन) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रणाली में डीपीआर परामर्शदाताओं

के पिछले निष्पादन कार्य के साथ-साथ उनकी साख और क्षमताओं का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और कार्य निष्पादन वापसी गारंटी पर बोली लगाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से राजमार्गों के निर्माण का एक तरीका है, जबकि इनविट मॉडल सरकार द्वारा अपनाए गए निर्मित राजमार्गों का मुद्रीकरण करना है। इस प्रकार, ईपीसी मोड का इनविट के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण किया है, जिसके अंतर्गत एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया (इनविट के मामले में सेबी-विनियमित बुक बिल्डिंग और बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया) के माध्यम से रियायतग्राहियों को केवल टोल अधिकारों की एक निश्चित अवधि के लिए नीलामी की जाती है, जिसके बाद टोल अधिकार सरकार को वापस कर दिए जाते हैं। सभी मामलों में, सड़क परिसंपत्तियाँ सरकार के पास निहित रहती हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क (टोल) लगाए जाते हैं।

*****